डीबीटी पर बज रहा यूपी का डंका

किसानों को लाभ

राज्य मुख्यालय | अजीत कुमार

बीजों की अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में भेजने की योजना ने पूरे देश में यूपी का डंका बजा दिया है। केन्द्र सरकार ने तो देश के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को बकायदा पत्र भेजकर उत्तर प्रदेश के बारे में कसीदे काढ़े हैं। कहा है कि पारदर्शिता के साथ किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने में यूपी मॉडल का जवाब नहीं है। सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए यूपी मॉडल को अपनाना चाहिए।

केन्द्र सरकार के पत्र के बाद कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, बिहार व तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने यूपी से सम्पर्क कर डीबीटी (अनुदान राशि सीधे खाते में डालने की योजना) के तरीकों की जानकारी मांगी है। केन्द्रीय कृषि सचिव की ओर से सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्रों में कहा गया है कि भारत सरकार चाहती है कि अनुदान के लिए आवंटित बजट केदुरुपयोग पर पूरी तरह से रोक लगे। इसके लिए सरकारी विभागों को बीज व अन्य चीजों पर दी जाने वाली सुविधाओं को डीबीटी से जोड़ा जाए ताकि किसानों या लाभार्थियों को सही मायने में लाभ मिल सके और बजट का दुरुपयोग भी रुक सके। पत्र में कहा गया है कि यूपी की डीबीटी योजना पूरी तरह से पारदर्शी है और इससे बेहतर और कोई इसका विकल्प नहीं हो सकता।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग ने पिछले साल के खरीफ सीजन में धान, मक्का व ज्वार-बाजरा के हाइब्रिड बीजों के वितरण में डीबीटी शुरु की थी। इसकी सफलता का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसान संगठनों ने हर स्तर पर इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कहा, गरीब किसानों को और कुछ मिले न मिले कम से कम इस योजना से अनुदान राशि तो मिल ही जा रहा है। लिहाजा संगठनों ने इस योजना को हर सीजन में लागू करने की मांग की। इस बीच खरीफ में मिली सफलता को देखते हुए यूपी ने रबी में भी डीबीटी लागू किया है जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण में भी राज्य सरकार ने इसे लागू करने के आदेश दिए हैं।

काबिले तारीफ

- केन्द्र ने सभी राज्यों को यूपी मॉडल अपनाने के दिए निर्देश
- यूपी के मॉडल की जमकर तारीफ कई राज्यों ने किया संपर्क
- कई राज्यों जैसे कर्नाटक , आंध्र प्रदेश ,पंजाब और हरियाणा ने योजना की जानकारी मांगी

क्या कहते हैं जिम्मेदार

किसानों को डीबीटी का सीधा फायदा पहुंचा है। योजना पूरी तरह से पारदर्शी है इसलिए इस पर सभी का विश्वास बढ़ रहा है।

मुकेश कुमार श्रीवास्तव, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश